

विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-11 का उत्तरालेख

प्रश्न

- 11 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित राजकीय इण्टर कालेज ओबरा के निजीकरण से इस विद्यालय में अध्ययनरत दूर-दराज के सैकड़ों अभावग्रस्त गरीब वंचित व आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायेंगे ?

(ख) क्या इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अन्य राजकीय विद्यालयों में समायोजन हेतु शासनादेश जारी करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

निगम के विद्यालय का निजीकरण नहीं किया गया है। मात्र उक्त विद्यालय के संचालन का कार्य डी0ए0वी0 द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति की देख-रेख में किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त समिति में दो वरिष्ठ सदस्य उत्पादन निगम लि0 द्वारा नामित होंगे।

विद्यालय का स्वामित्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पास संरक्षित है।

विगत में उत्पादन निगम लि0 द्वारा संचालित ओबरा इण्टर कालेज ओबरा में अध्ययनरत विद्यार्थी पूर्व में भी निगम के नियमानुसार शिक्षा शुल्क दे रहे थे एवं वर्तमान व्यवस्था में भी यह पूर्वानुरूप लागू रहेगी।

ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र जनपद के एक दूरस्थ एवं अविकसित क्षेत्र में अवस्थित है। परियोजनान्तर्गत कार्यरत कर्मिकों एवं स्थानीय नागरिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु निगमीय विद्यालय की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री